



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2010/फाल्गुन 12, 1931

No. 446]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2010/PHALGUNA 12, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2010

सं. 33/2009-2014

विषय :—गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक—छूट के संबंध में।

का.आ. 530(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.3 और पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या 93(आर ई-2007)/2004-2009, दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 38 (आर ई-2007)/2004-2009, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है।

2. अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-2009, दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पैरा 2.1 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“2.1.11 पी.ई.सी. के माध्यम से श्री लंका को 20,000 मी. टन चावल (पोनी साम्बा) के निर्यात पर भी गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी।

2.1.12 एम.एम.टी.सी. के माध्यम से नेपाल को 25,000 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी।”

3. उपर्युक्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

(क) निर्यात किए जाने वाले चावल में न्यूनतम 25% टूटा चावल होना चाहिए।

(ख) निर्यात प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और यह केवल नामित पी एस यू द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भी सहायक निर्यातक नहीं होगा।

(ग) प्रापक देश को गैट के प्रावधानों के अनुसार विदेश मंत्रालय के द्वारा केवल नामित सार्वजनिक उद्यम की इकाइयों के साथ निर्यातों के ठेकों को करने के लिए कहा जाएगा और चावल निर्यात करने के लिए आयातक देश के द्वारा निजी ठेकेदार पर विचार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय संबंधित सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) को आयातक देश में नामित खरीदने वाली एजेंसी को सूचित करेगा।

(घ) सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) वाणिज्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/4/2009-एफटी (एसटी) दिनांक 18-2-2010 के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सविदा के द्वारा चावल प्राप्त करेंगे।

(ङ) सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) पूरे देश के बाजार से चावल खरीदेंगे। आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को यह सुनिश्चित करते हुए कि चावल को प्राप्त कर लिया गया है, को आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे। आपूर्तिकर्ता इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे कि चावल को उन मिलों से प्राप्त किया गया है जिन्होंने पहले ही अपनी लैवी चावल आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।

(च) सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) बाजार से यथा सम्भव ऐसे मूल्य पर खरीद करेगी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) के निकट हो ताकि बाजार में मौजूदा मूल्य स्थिति को प्रभावित न करे।

(छ) सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) खरीद निविदा या अन्य किसी तरीके से कर सकती है किन्तु ऐसा वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

(ज) गन्तव्य पर पहुँचने पर निर्यातों की अन्तिम जाँच सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) द्वारा प्रस्तुत की जाएगी; और इस हेतु पीएसयू निष्पत्ति के पत्तन (पत्तनों) से लैंडिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

(झ) उपर्युक्त मात्रा को के.एम.एस. 2009-2010 के दौरान सार्वजनिक उद्यम (पी एस यू) द्वारा निर्यात की जाएगी।

4. अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-09 दिनांक 1-4-2008 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे तथा लागू रहेंगे।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/775/एम 10/एक्सपोर्ट सैल]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN
TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2010

No. 33/2009-2014

**Subject : Prohibition on Export of Non-basmati Rice—
Exemption regarding.**

S.O. 530(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) and also read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendment to Notification No. 38 (RE-2007)/2004-2009, dated 15-10-2007 read with Notification No. 93 (RE-2007)/2004-2009 dated 1-4-2008, as amended from time to time.

2. Following shall be added at the end of Para 2.1 of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004-2009, dated 1st April, 2008:

“2.1.11 With immediate effect, ban on export of Non-basmati rice shall also not be applicable to export of 20,000 MT of rice (Ponni Samba) to Sri Lanka through PEC.

2.1.12 With immediate effect, ban on export of Non-basmati rice shall also not be applicable to export of 25,000 MT of Non-basmati rice to Nepal through MMTC.”

3. The above export shall be subject to the following conditions :

- (a) The rice to be exported shall be with a minimum of 25% of broken;
- (b) Export will be undertaken directly, and only by the designated PSU/s. There will not be any associate exporter;
- (c) Recipient country will be advised by MEA to enter into contracts for the exports only with the designated PSUs, in terms of GATT provisions and designation of a private contractor by the importing country, to supply rice will not be entertained. MEA will inform the concerned PSU(s) about the designated buying agency in the importing country;
- (d) The PSU/s will procure rice through tender as per guidelines prescribed by the Department of Commerce vide O. M. No. 7/4/2009-FT(ST) dated 18-2-2010;
- (e) The PSU(s) will buy rice from the markets all over the country. The Supplier(s) will provide the necessary certificate to the PSU(s) confirming that rice has been procured to this effect. The supplier(s) will also provide a certificate to the effect that the rice is bought from those rice mills who have already met their levy rice requirements as stipulated in their respective States.
- (f) The PSU/s will procure rice at a price as close to as possible to the derived MSP so as not to disturb the existing price situation in the domestic market;
- (g) PSU(s) will supply rice to the designated country at a commercially negotiated price;
- (h) The end point verification of the exports reaching the destination will be filed by the PSU(s) and for this purpose, the PSU(s) will obtain landing certificates from the port(s) of discharges;
- (i) The above quantity shall be exported by PSUs during KMS 2009-10.

4. All other provisions of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004-09 dated 1st April, 2008, as amended from time to time, shall remain unchanged, and shall continue to apply.

5. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/180/775/AM 10/Export Cell]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade &
ex-officio Spl. Secy.